संपादकीय

नापाक मंसूबे विफल

दो साल पहले हुए भयावह पुलवामा हमले वाले दिन फिर बड़ी आतंकी वारदात दोहराने की साजिश का पर्दाफाश होने से देश ने राहत की सांस ली है। यदि सुरक्षा बल सतर्कता न बरतते तो एक बार फिर देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। दरअसल, सुरक्षा बलों को इस बात की भनक तो थी कि पाक पोषित आतंकवादी एक बार फिर पुलवामा की बरसी पर देश को आतंक से दहलाना चाहते हैं। लेकिन इसे सुरक्षा चूक ही माना जायेगा कि कैसे आतंकी विस्फोटक सामग्री जम्मू बस अड्डे के करीब तक ले जाने में कामयाब रहे।दरअसल, जम्मू पुलिस ने रविवार की सुबह बस स्टैंड से करीब सात किलो आईईडी समेत एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया था। यह भी चिंता की बात है कि चंडीगढ़ में पढ़ने वाले एक नर्सिंग के छात्र को कैसे मोहरा बनाया गया। उसे पाक में बैठे आकाओं ने संदेश भेजकर बताया था कि उसे कहां-कहां आईईडी प्लांट करने हैं। सात किलो आईईडी और अन्य हथियारों की बरामदगी आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को ही उजागर करती है जो सुरक्षा बलों को अधिक चौकस होने की जरूरत बताता है। जिस सोहेल नामक छात्र को आईईडी के साथ गिरफ्तार किया गया, उसे पाक स्थित अल बदर तंजीम द्वारा आईईडी प्लांट करने के निर्देशमिल रहे थे। उसे चार भीड़भाड़ वाले इलाकों को लक्ष्य बनाने को कहा गया था और उसके बाद फ्लाइट से श्रीनगर भाग जाना था।यह भी तय था कि श्रीनगर में उसे किस संगठन से संरक्षण मिलेगा। इस साजिशमें शामिल चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद है कि इस साजिश के कुछ और राज सुरक्षा बलों को मिलेंगे। इसके साथ ही सांबा सेक्टर से 15 छोटे आईईडी और छह पिस्तौलें भी बरामद की गई हैं। दो साल पहले पाक की साजिशके चलते जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा कांड को अंजाम दिया था। विस्फोटों से लदे वाहन की सीआरपीएफ के जवानों की बस से टक्कर मार दी गई थी, जिसमें चालीस जवान शहीद हुए थे। जिसके बाद भारत ने बालाकोटमें आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद करके पाक को सबक सिखाया था।

हाल के दिनों में पाक ने भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते अपनी आतंकी रणनीति में बदलाव किया है। वह पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों को मोहरा बनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है।वह दिल्ली समेत कई अन्य स्थलों को निशाने पर ले रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के कार्यालय की रेकी करके वीडियो बनाया गया, जिससे आतंकियों के खतरनाक इरादों का पता चलता है। जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गे दिल्ली को दहलाने की फिराक में हैं। नयी जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन बिहार से हथियार खरीद रहे हैं और पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों को इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इन हथियारों को कश्मीर घाटी तक पहुंचाया जा सके।कुछ आतंकी संगठनों के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद ये तथ्य सामने आये हैं। सांबा क्षेत्र में तेरह फरवरी को गिरफ्तार कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अनुषांगिक संगठन से जुड़े हैं।इनके कुछ सदस्य बड़ी बैंक लूट में भी शामिल रहे हैं ताकि आतंकी गतिविधियों के संचालन के लिये धन जुटाया जा सके। इसके कुछ सदस्यों ने पाक में प्रशिक्षण लेने के बाद स्थानीय स्तर पर संगठन खड़े किये हैं। इस नेटवर्क में सेंध लगाकर पुलिस ने आठ आतंकियों की पहचान करके कार्रवाई शुरू की है।कश्मीर में सख्ती के चलते ये आतंकी संगठन जम्मू को अपना गढ़ बनाने की फिराक में हैं ताकि अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। दरअसल, पाक ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए जहां ड्रोन व सुरंगों के जरिये आतंकी व हथियार भारत भेजने की रणनीति बनायी है, वहीं स्थानीय आतंकी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछसमय में जम्मू क्षेत्र में छह भूमिगत सुरंगों का पता चला है, जिनके जरिये हथियार-आतंकी भारत पहुंचते हैं।

चीनी सेना की वापसी के गहरे निहितार्थ

विश्लेषण

पी. स्टोबडन

लद्दाख की सीमा पर विवाद स्थल से दोनों पक्षों के सैनिकों की पुरानी जगह पर वापसी होना अपेक्षित था। यही कुछ पूर्व में भारत-चीन तनातनी के बाद हुआ था। लेकिन सीमा पर स्थायित्व बनने में काफी लंबा वक्त लगता है। समझौते के मुताबिक जल्द ही दोनों ओर के सैनिक चरणों में पैंगोंग इलाके में बनाए गए अग्रिम मोर्चों से पीछे हटेंगे, जिसका अर्थ है कि अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बनना-भारतीय सेना फिंगर 3 पहाड़ी पर स्थित अपनी रिवायती धन सिंह चौकी पर लौट आएगी तो चीनी पीएलए सैनिक झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 पर स्थित सीरिजाब चौकी पर। इसी तरह झील के दक्षिणी किनारे पर भी पुरानी यथास्थिति बहाल की जाएगी। दोनों देश अप्रैल 2020 के बाद उकेरे गए ढांचे हटा देंगे और इस क्षेत्र में रिवायती गश्त मुल्तवी रखी जाएगी।

जैसा कि रक्षा मंत्री ने संसद को आश्वस्त किया है कि भारत ने सीमा विवाद पर चीनी दावे पर कुछ भी बेजा स्वीकार नहीं किया है। देपसांग और देमचोक क्षेत्र में भी जो अनसुलझे मामले हैं, उन्हें आगे की वार्ता से हल किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा विवाद का हल द्विपक्षीय मसविदे के अनुसार निकाला गया है।

तो अब किन वजहों से सैनिक वापसी संभव हो पाई है बिना शक लद्दाख में चीन की चाल गंदली है, लेकिन फिलहाल जिस समय उसने पीछे हटना माना है, कारणों का विश्लेषण करें तो सभवत: यह चीन का सामरिक दांव है, शायद इसके छिपा कारण है लद्दाख के तनाव में अमेरिका का दाखिल होना। 12 जनवरी को जारी किए अमेरिकी सामरिक दस्तावेज में चीन को नाथने वाली योजना किसी से छिपाई नहीं गई।

इस पूरे समय में अमेरिका ने चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेवार मानकर उसे व्यापार एवं तकनीक क्षेत्र में सबक सिखाने के प्रयासों में भारत को बतौर एक इच्छुक साझेदार की तरह पेश किया है, चीन से व्यापारिक संबंध तोड़ने के लिए महामारी भी बहाना रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने विदाई भाषण में भारत से मिलकर बनाई विस्तृत साझेदारी की बात स्वीकारी है। अमेरिका के पूर्व राजदूत कैनेथ जस्टर ने रहस्योद्घाटन किया है कि अमेरिका ने समूचे लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैन्य और कुमुक संबंधी गतिविधियों की पूर्व सूचना भारत के साथ वास्तविक समय में साझा की थी ताकि वक्त रहते इंतजाम किया जा सके। हालांकि भारत और चीन ने ट्रंप द्वारा मध्यस्थता करने की पेशकश को खारिज कर दिया था, दोनों पक्षों ने झगड़े का शांतिपूर्ण हल आपसी वार्ता से करने की बात दोहराई थी। ट्रंप प्रशासन का समय चुकते पाकर चीन ने सैनिक पीछे हटाने की पहली पेशकश नवम्बर माह में करते हुए सिरिजाप फिंगर क्षेत्र को सैनिक-रहित इलाका बनाने का प्रस्ताव दिया था। तब भारत द्वारा इसको स्वीकार करने का मतलब होता इलाके में रिवायती गश्त के हक से महरूम होना। बाद में पीएलए ने अपने 10000 सैनिक वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा से हटाकर अंदरूनी इलाकों (80 से 100 कि. मी.) में भेज दिए थे। बेशक तनाव में कमी की शुरुआत उसी वक्त से होने लगी थी, किंतु चीन ने संभवत: तब तक आगे की वार्ता से खुद को रोके रखा जब तक कि ट्रंप शासन की आखिरी घड़ी न आन पहुंचे।

प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट है = भारत-अमेरिकी सामरिक साझेदारी की ताजा सीमा रेखा को चीन परखना चाहता है और अपने विकल्प तोलने के लिए इस बात के इंतजार में है कि विशेषतौर पर उसको केंद्र में रखकर बनाए गए चार देशों के क्वाड नामक गठबंधन और हिंद-प्रशांत रणनीति पर बाइडेन प्रशासन क्या रुख अपनाता है। अब तक जो कुछ पता चला है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुए हालिया संवाद में क्वाड को लेकर मतांतर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन और भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के मध्य हुई बातचीत के बाद 29 जनवरी को जारी विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में भी क्वाड को लेकर कोई जिक्र नहीं है। क्वाड को एक विशिष्ट सैन्य गठजोड़ का स्वरूप देने पर भारत की हिचकिचाहट पहले से सर्वविदित है। अभी भी भारत अमेरिका द्वारा बुलाई गई अगले स्तर की बैठक में भाग लेने में अनिच्छुक है। सवाल यह है कि क्या चीन के साथ तनाव में कमी होना अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन तंत्र में भारत के भाग न लेने से जुड़ा है।

इसी बीच अमेरिका और भारत में मतभेद होने के संकेत तब से उभरते दिखाई देने लगे हैं जब अमेरिकी संसद की भारत-निगरान कमेटी ने किसान आंदोलन से निपटने में मोदी सरकार द्वारा अपनाए अलोकतांत्रिक तौर-तरीकों पर चिंता जताई है, जिसके तहत इंटरनेट बंद करना और ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए बनाया गए दबाव शामिल हैं। कश्मीर मामलों को लेकर भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपवाद स्वरूप कड़ा वक्तव्य जारी किया है। म्यांमार में अमेरिका द्वारा अपनाए सख्त रुख की ताईद भारत द्वारा न करना मतभेद का एक अन्य बिंदु बनकर उभरा है।

नयी बनी उक्त पृष्ठभूमि के मद्देनजर चीनी रक्षा मंत्री ने तुरत-फुरत लद्दाख गतिरोध खत्म करने का कदम उठा लिया, भारत द्वारा बयान जारी करने के एक दिन पहले ही! चीनी विश्लेषकों का मानना है कि भारत के घरेलू मसलों और पाक-अफगान कारक पर बनने वाले मतभेदों के अलावा रूस निर्मित एस-400 मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली की खरीद पर अमेरिका के संभावित प्रतिबंध से दोनों मुल्कों के बीच तनाव पैदा होगा। चीनी मीडिया के अनुसार भारत द्वारा बेसिस एक्सचेंज एंड कॉ-ऑपरेशन एग्रीमेंट (बेका) नामक संधि हस्ताक्षर करना चीन से उपजे खतरे से संतुलन बिठाने की बजाय उलटे अपनी सामरिक संप्रभुता से समझौता करना होगा। वास्तव में, कैनेथ जस्टर ने भी चीनी कारक की वजह से भारत-अमेरिका के बीच उपजते मतभेद के तथ्य का हवाला देते हुए कहा है कि लगता है भारत-अमेरिकी संबंध विपरीत दिशा में जाने वाले हैं।

दूसरी ओर चीनियों ने भारत-चीन समीकरण में अमेरिकी कारक को नहीं गिना, उन्हें लगता है कि इनका निर्धारण मोटे तौर पर ढांचागत मसलों पर अपनाई गई लीक से होगा और इनको द्विपक्षीय माध्यमों से सुलझाया जा सकता है। अतएव स्पष्ट है, लद्दाख में चीनियों द्वारा पीछे हटने का निर्णय बाइडेन द्वारा सत्ता संभालने के ठीक बाद आया है और इसका उद्देश्य भारत-अमेरिका द्वारा चीन केंद्रित गठजोड़ जारी रखने की संभावना क्षीण करना है। चीन का बनता झुकाव ऐसे वक्त पर आया है जब बाइडेन प्रशासन का क्वाड गुट पर अपनी नीति को औपचारिक रूप देना बाकी है।

इतना तय है कि चीन 1962 वाला ढंग नहीं दोहरा पाया। 1962 की हार से हम पर जो मनोवैज्ञानिक हौवा लगातार हावी रहा था, उसे अब हमेशा के लिए मिटा दिया गया है।

हालांकि यह बात भी पक्की है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब तक जो भी आरंभिक कदम उठाए गए हैं, वे संकेत देते हैं कि स्पानगुर खड्ड के सामने पड़ते पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित पहाड़ियों की ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को नीचे नहीं उतारा गया है। तथापि श्लाघायोग्य हिस्सा यह है कि जहां दोनों मुल्कों ने स्थिति सामान्य बनाने हेतु माकूल समय एवं विस्तार देकर उदाहरणीय कदम उठाए हैं, वहीं अपनी-अपनी जनता की विरोध-प्रतिक्रिया से बचने को यथेष्ठ समय लेने की सावधानी बरती है।

भूकंप:सचेत रहने से ही बनेगी बात

दृष्टिकोण

पंकज चतुर्वेदी

भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर टिका है, और हमारे यहां अधिकतर भूकंप इस प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण उपजते हैं। भूकंप के झटकों का कारण भूगर्भ से तनाव-ऊर्जा उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा अब भारतीय प्लेट की उत्तर दिशा में बढ़ने और फॉल्ट या कमजोर जोनों के जरिए यूरेशियन प्लेट के साथ इसके टकराने के चलते एकत्र हुई है।

वर्ष 2020 में दिल्ली और उसके आसपास के दायरे में कुल 51 बार घरती थर्राई। भारत के कुल क्षेत्रफल का 54 फीसद भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित है।दिल्ली को खतरे के लिए तय जोन चार में आंका गया है अर्थात यहां भूकंप आने की संभावनाएं गंभीर स्तर पर हैं। भूकंप संपत्ति और जन-हानि के नजरिए से सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा है, एक तो इसका सटीक पूर्वानुमान संभव नहीं, दूसरा इससे बचने के कोई सशक्त तरीके हैं नहीं। महज जागरूकता और अपने आसपास को इस तरह से सचेत करना कि कभी भी धरती हिल सकती है, बस यही है इसका निदान। हमारी धरती जिन सात टेक्टोनिक प्लेटों पर टिकी है, यदि इनमें कोई हलचल होती है, तो धरती कांपती है।

भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर टिका है, और हमारे यहां अधिकतर भूकंप इस प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण उपजते हैं। भूकंप के झटकों का कारण भूगर्भ से तनाव-ऊर्जा उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा अब भारतीय प्लेट की उत्तर दिशा में बढ़ने और फॉल्ट या कमजोर जोनों के जरिए यूरेशियन प्लेट के साथ इसके टकराने के चलते एकत्र हुई है। जानना जरूरी है कि हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र में भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव होता है, और इसी से प्लेट बाउंड्री पर तनाव ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, जिससे क्रिस्टल छोटा हो जाता है, और चट्टानों का विरुपण होता है। यह ऊर्जा भूकंपों के रूप में कमजोर जोनों एवं फाल्टों के जरिए सामने आती है। हालांकि कोई भूकंप कब, कहां और कितनी अधिक ऊर्जा (मैगनिटयूड) के साथ आ सकता है, इसकी अभी कोई सटीक तकनीकी विकसित हो नहीं पाई है, केवल किसी क्षेत्र की अति संवेदनशीलता को उसकी पूर्व भूकंपनीयता, तनाव बजट की गणना, सक्रिय फाल्टों की मैपिंग आदि से समझा जा सकता है।

आज जरूरी है कि जिन इलाकों में बार-बार धरती डोल रही है, वहां भू वैज्ञानिक अध्ययनों का पूरी तरह उपयोग करते हुए उपसतही संरचनाओं, ज्यामिति तथा फाल्टों एवं रिजों के विन्यास की जांच की जानी है। चूंकि नरम मृदाएं संरचना की बुनियादों को सहारा नहीं दे पातीं, भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में बेडरॉक या सख्त मृदा के सहारे वाली संरचनाओं में कम नुकसान होता है। इस प्रकार, नरम मृदाओं की मोटाई के बारे में जानने के लिए मृदा द्रवीकरण अध्ययन किए जाने की भी आवयकता है। सक्रिय फाल्टों को निरूपित किया जाना है, और जीवन रेखा संरचनाओं या अन्य अवसंरचनाओं को नजदीक की सक्रिय फाल्टों से बचा कर रखे जाने और उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। राट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सवा तीन करोड़ लोगों की बसावट का चालीस फीसदी इलाका अनधिकृत है, तो 20 फीसदी के आसपास बहुत पुराने निर्माण। बाकी रिहाइशों में से बामुश्किल पांच प्रतिशत का निर्माण या उसके बाद यह सत्यापित किया जा सका कि यह भूकंपरोधी है। दोष भारत में भी आवासीय परिसरों के हालात कोई अलग नहीं हैं। एक तो लोग इस चेतावनी को गंभीरता से ले नहीं रहे कि उनका इलका भूकंप के आलोक में कितना संवेदनशील है, दूसरा उनका लोभ उनके घरों को संभावित मौत घर बना रहा है। बहुमंजिला मकान, छोटे से जमीन के टुकड़े पर एक के ऊपर एक डिब्बे जैसी संरचना, बगैर किसी इंजीनियर की सलाह के बने परिसर, छोटे से घर में ही संकरे स्थान पर रखे ढेर सारे उपकरण व फर्नीचर-भूकंप के खतरे से बचने की चेतावनियों को नजरअंदाज करने की मजबूरी भी हैं और कोताही भी।

वलेरेबिलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बिल्डिंग मैटीरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली के 91.7 प्रतिशत मकानों की दीवारें पक्की ईटों से जबकि कच्ची ईंटों से 3.7 प्रतिशत मकानों की दीवारें बनी हैं। एक्सपर्ट के अनुसार, कच्ची या पक्की ईटों से बनी इमारतों में भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा तबाही होती है। राट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद के एक शोध से स्पष्ट हुआ है कि भूकंप का एक बड़ा कारण धरती की कोख से जल का अंधाधुंध दोहन करना भी है। भू-विज्ञानी के अनुसार भूजल को धरती के भीतर लोड यानी की एक भार के तौर पर उपस्थित होता है। इसी लोड के चलते फाल्ट लाइनों में भी संतुलन बना रहता है।

जरूरत है कि शहरों में आबादी का घनत्व कम किया जाए, जमीन पर मिट्टी की ताकत मापे बगैर कई मंजिला भवन खड़े करने, बेसमेंट बनाने पर रोक लगे। भूजल के दोहन पर सख्ती हो। साथ ही, भूकंप संभावित इलाकों के सभी मकानों में भूकंप रोधी रेट्रोफिटिंग करवाई जाए।

आजकल

साजिश का खुलासा जरूरी

गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली और लाल किले में हिंसा फैलाने का दायरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। नये कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलनरत किसानों को साजिश के तहत भड़काने और अंतरराट्रीय स्तर पर देश की छवि या कहें देश के खिलाफ माहौल बनाने के लिए टूलकिट बनाने में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने पहली गिरफ्तारी की है। बेंगलुरू से टूलकिट बनाने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर साजिश की परतें खोलेंगी। पुलिस को फिलहाल अभी दो और लोगों की तलाश है। साथ ही दिशा के मोबाइल और लैपटॉप से कई अहम जानकारियां भी वापस लेनी, जो गायब हैं। इसके बाद पूरा मसला ज्यादा साफ तरीके से सामने आएगा। हां, साजिश के आरोपों की आंशिक पुष्टि दिशा की स्वीकारोक्ति से हो गई है कि उसने टूलकिट में संपादन किया था।

यह तो जगजाहिर है कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो भारी हिंसा भड़की, वह बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। शुरुआती जांच में यही पता लग पाया था कि इस पूरी वारदात के पीछे खालिस्तान समर्थकों की बड़ी भूमिका है। 4 फरवरी को इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और 11 दिन बाद दिशा की गिरफ्तारी से जांच का सिरा कई और साजिशकर्ताओं की तरफ चला गया है। दरअसल, जिस वक्त अमेरिका की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट शेयर किया था, तब दिशा ने ही ग्रेटा को चेताया था कि टूलकिट पब्लिक डोमेन में चला गया है। बाद में ग्रेटा ने इसे डिलीट कर दिया था। लाजिमी है कि गलत होने पर ही इसे ट्वीट किया गया था। दूसरी अहम बात यह भी कि अगर किसी तरह का षडयंत्र नहीं किया गया तो लिखी चीजें क्यों डिलीट की गई

यानी माहौल बिगाड़ने के लिए ही टूलकिट बनाया गया था। जो जांच अभी तक की गई है उसमें सबसे चिंता की बात यह है कि इस टूलकिट को बनाने में खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाऊंडेशन की अहम भूमिका है। साफ है कि देश विरोधी तत्व एकजुट होकर किसान आंदोलन की आड़ में साजिश रच रहीं हैं। इसके बावजूद पुलिस को बेहद ईमानदारी के साथ मामले की जांच करनी होगी। चूंकि विपक्ष की गोलबंदी भी दिशा की गिरफ्तारी को लेकर तेज हो चली है तो यह जांच एजेंसी का दायित्व है कि वह साफ-सुथरे ढंग से हर किसी की आपत्ति या सवालों का जवाब दे। अगर वाकई में देश को अस्थिर करने का षडयंत्र रचा जा रहा है तो इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

महंगाई का ईंधन

मुद्दा

फीचर

भारतीय पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही हैं। इसका नतीजा यह है कि देश के ज्यादातर शहरों में इसकी कीमत नब्बे से सौ रुपए के बीच पहुंच गई है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में यह कीमत सौ रुपए से भी अधिक हो गई है। यही हाल घरेलू गैस का है।

इस महीने करीब बारह दिनों में ही एक सिलिंडर की कीमत पचहत्तर रुपए बढ़ गई। इसे लेकर स्वाभाविक ही आम लोगों में निराशा और नाराजगी है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर भी दिखाई देने लगता है। माल ढुलाई और यातायात खर्च बढ़ जाता है। कल-कारखानों में उत्पादन लागत ऊंची हो जाती है। यानी कुल मिला कर आम नागरिकों की जेब पर चौतरफा बोझ पड़ता है।

आमतौर पर अंतरराट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। मगर अनेक मौकों पर देखा गया है कि जब अंतरराट्रीय बाजार में कीमतें काफी कम रही हैं, तब भी हमारे यहां तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इस वक्त भी कच्चे तेल की कीमतें इतनी अधिक नहीं हैं कि उसका बोझ डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा कर कम किया जाए। जब केंद्र में भाजपा की अगुआई वाली सरकार पहली बार आई थी, तब अंतरराट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो गई थीं।

उस वक्त सरकार ने एलान किया था कि वह तेल की कीमतें कम नहीं करेगी, एक विशेष कर के रूप में उसे एकत्र कर एक तेल पूल तैयार करेगी, जो संकट के समय काम आएगा। वह कर लगातार बढ़ता गया है, पर अब तक न तो उस एकत्र पैसे से कोई तेल पूल तैयार किया गया है और न ऐसा कोई उपाय, जिससे जब अंतरराट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हों, तो अधिक से अधिक कच्चा तेल खरीद कर रखा और तेल की कीमतें संतुलित रखी जा सकें। गनीमत है कि पिछले साल जब इसी तरह तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थीं, तो कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां वैट दरें घटा दी थीं, जिससे कीमतें कुछ राहत देने वाली हो सकी थीं। मगर राज्य सरकारों की भी अपनी सीमा है, वे बार-बार ऐसा नहीं कर सकतीं।

विचित्र है कि ऐसे समय में, जब बहुत सारे छोटे और मझोले उद्योग, रेहड़ी-पटरी के कारोबार, दुकानें आदि बंद हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लाखों लोगों को पहले से कम वेतन पर गुजारा करना पड़ रहा है, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, तब भी तेल की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं हो रहा।

सरकार का दावा है कि जल्दी ही अर्थव्यवस्था ऋणात्मक स्तर से ऊपर उठ कर धनात्मक रुख कर लेगी, मगर हकीकत यह है कि दुनिया के एक सौ तिरानबे देशों में विकास दर के मामले में भारत की स्थिति एक सौ साठ से भी नीचे के पायदान पर पहुंच चुकी है। इस स्थिति में तेल और घरेलू गैस जैसी वस्तुओं के दाम को सरकार अगर संभाल नहीं पा रही, तो उसके लिए महंगाई और अर्थव्यवस्था की चुनौती से पार पाना कठिन ही रहने वाला है।